



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 2004/आषाढ़ 11, 1926

No. 114]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 2004/ASADHA 11, 1926

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

मुख्य, 29 जून, 2004

सं. टीएमपी/103/2001-सीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा हल्दिया में कोलकाता पत्तन न्यास के भूखंड और भवनों की वर्तमान दर अनुसूची की वैधता का, संलग्न आदेशानुसार, विस्तार करता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएमपी/103/2001-सीपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास

आवेदक

## आदेश

(जून, 2004 के 22वें दिन पारित)

यह प्रकरण हल्दिया में कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के भूखंड और भवनों की वर्तमान दर अनुसूची की वैधता को 30 जून, 2004 से आगे विस्तार प्रदान करने से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने हल्दिया में भूखंड और भवनों की वर्तमान दर अनुसूची की वैधता को 30 जून, 2004 अथवा संशोधित किराया अनुसूची की अधिसूचना तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करने के लिए 16 दिसंबर, 2003 को एक आदेश पारित किया था।

3. केओपीटी ने अपने दिनांक 17 जून, 2004 के पत्र द्वारा इस प्राधिकरण से हल्दिया में केओपीटी के भूखंड और भवनों की वर्तमान दर अनुसूची की वैधता को 31 दिसंबर, 2004 अथवा संशोधित किराया अनुसूची की अधिसूचना तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में केओपीटी द्वारा कही गई मुख्य बांध निम्नलिखित हैं—

- (i) केओपीटी ने हल्दिया में अपने भूखंड और भवनों की किराया अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया है।
- (ii) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने केओपीटी को उक्त प्रस्ताव की भारत सरकार द्वारा हाल ही में महापत्तन के लिए तैयार की गई भूखंड नीति के महेनपर समीक्षा करने की सलाह दी थी।

(iii) भारत सरकार द्वारा हाल ही में महापत्तनों के लिए तैयार की गई भूखंड नीति एमबीपीटी और केओपीटी पर लागू नहीं होती है। केन्द्र सरकार से केओपीटी के लिए भूखंड नीति प्राप्त होने पर महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा दी गई सलाह पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। केओपीटी को उस पर लागू भूखंड नीति अभी प्राप्त नहीं हुई। इस मामले में सरकार से आग्रह किया जा रहा है।

(iv) हल्दिया में केओपीटी के भूखंड और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची 30 जून, 2004 को समाप्त हो जाएगी और इसलिए वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को 30 जून, 2004 से आगे विस्तारित करना आवश्यक है।

4. केन्द्र सरकार द्वारा पत्तन सम्बद्धाओं के पट्टे के मामले में जारी मार्गदर्शियों को इस प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया है और दरमान तथा शर्तों का विवरण तैयार करने के प्रयोजन से उनका अनुसरण किया गया है। केओपीटी की परिसम्पत्तियों के लिए वर्तमान भूखंड नीति भारत सरकार के समक्ष समीक्षाधीन है। केओपीटी ने हल्दिया में भूखंड और भवनों की दर अनुसूची में संशोधन करने के लिए इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। केओपीटी के लिए भारत सरकार से नई भूखंड नीति प्राप्त होने पर केओपीटी अपने प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए सहमत हो गया है।

5. पत्तन से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्ताव पर कार्यवाही करने में समय लगेगा। चूंकि, हल्दिया में भूखंड और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता 30 जून, 2004 को समाप्त हो जाएगी और 30 जून, 2004 के पश्चात भूखंड और भवनों के पट्टा किरायों में शून्यता नहीं रह सकती, इसलिए हल्दिया में केओपीटी के भूखंड और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को 30 जून, 2004 से आगे विस्तारित करना आवश्यक है।

6. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण हल्दिया में केओपीटी के भूखंड और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता का 31 दिसंबर, 2004 अथवा संशोधित किराया अनुसूची की अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है।

ज. ल. बोगिंगपार, अध्यक्ष

[ विज्ञापन- III/IV/143/04-असाधारण ]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 29th June, 2004

No. TAMP/103/2001-CPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Schedule of Rates for land and buildings of the Kolkata Port Trust at Haldia as in the Order appeared hereto.

## Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/103/2001-CPT

The Kolkata Port Trust

Applicant

### ORDER

( Passed on this 22 day of June 2004 )

This case relates to extension of the validity of the existing Schedule of Rates for land and buildings of the Kolkata Port Trust (KOPT) at Haldia beyond 30 June 2004.

2. This Authority had passed an order on 16 December 2003 extending the validity of the existing rent schedule for land and buildings at Haldia till 30 June 2004 or notification of the revised rent schedule whichever is earlier.

3. The KOPT vide its letter dated 17 June 2004 has requested the Authority to extend the validity of existing Schedule of Rates for land and buildings of KOPT at Haldia till 31 December 2004 or notification of the revised rent schedule whichever is earlier. The main points made by the KOPT in this regard are as follows:

- (i). KOPT has filed the proposal for revision of the Schedule of Rent for land and buildings of KOPT at Haldia for approval.
- (ii). TAMP advised KOPT to review the said proposal in the light of the Land Policy for major ports framed by the Government of India recently.
- (iii). The Land Policy for major ports recently framed by the Government is not applicable for MBPT and KOPT. Necessary action as advised by TAMP would be taken on receipt of Land Policy for KOPT from the Central Government. KOPT has not received the land policy applicable for it. The government is being pursued in the matter.
- (iv). The existing Rent Schedule for land and buildings of the KOPT at Haldia will expire on 30 June 2004 and it is necessary to extend the validity of the existing rent schedule beyond 30 June 2004.

4. The Guidelines issued by the Central Government in the matter of leases of port estates have been adopted and followed by this Authority for the purpose of framing Scale of Rates and statement of conditions. The existing land policy for the estates of KOPT is under review by the Government of India. The KOPT has filed a proposal before this Authority for revision of Schedule of Rent for land and buildings at Haldia. The KOPT has agreed to review its proposal on receipt of new land policy for KOPT from the Government of India.

5. Processing of the revised proposal to be received from the Port will take time. Since, the validity of the existing Schedule of Rent for land and buildings at Haldia will expire on 30 June 2004 and there cannot be a vacuum in lease rentals for land and buildings after 30 June 2004, it is necessary to extend the validity of the existing Rent Schedule for land and buildings of the KOPT at Haldia beyond 30 June 2004.

6. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing Rent Schedule for land and buildings of the KOPT at Haldia till 31 December 2004 or date of effect of Notification of the revised Rent Schedule whichever is earlier.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT III/IV/143/04-Exty]